को अच्छी फिल्में बना कर दे सकेंगे, सुन्दर और स्वस्थ फिल्में दे सकेंगे।

18.14. hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Seventeenth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): I beg to present the Seventeenth Report of the Business Advisory Committee.

श्री इसहाक साम्भली (अमरोहा): उपाध्यक्ष महोदय, वहां यह तय किया गया था कि पूरा दिन दिया जायेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: When it would be circulated, it will come before the House tomorrow.

श्री इसहाक साम्भली: मैं करेक्ट कर रहा हूँ। वहां यह तय हुआ था कि आफ्टर क्वेश्चन -- आवर, फुल डे डिस्कशन होगा।

DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69—*Contd*

Ministry of Information and Broadcasting—*Contd.*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़): उपाध्यक्ष महोदय, भारत में स्वतन्त्रता के बाद जब केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् के विभागों का वितरण हुआ तब आकाशवाणी या रेडियो का यह विभाग सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वयं अपने हाथों में रक्खा। इस से इस बात का परिचय मिलता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल और उस समय की सरकार इस विभाग को कितना महत्वपूर्ण विभाग मानती थी। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया, सरदार के बाद जिन के हाथों में यह विभाग रहा उन में से कुछ को छोड़ कर शेष ने इस विभाग को जितनी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये था और जो सतर्कता इस विभाग के साथ बरती जानी चाहिये थी उस प्रकार की सतर्कता नहीं बरती। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूँ।

आकाशवाणी जो प्रचार का सब से प्रमुख माध्यम देश में बना हुआ है, उस में दो प्रकार के व्यक्तियों की भरमार है। एक वह जो साम्यवादी विचारों से प्रभावित हैं। और दूसरे वह जो सम्प्रदायवादी विचारों से प्रभावित हैं। आकाशवाणी से कुछ कार्यक्रम प्रति दिन प्रसारित हैं। लेकिन उन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये जिन व्यक्तियों का उपयोग होता है उन की अपनी विचारधारायें और जिन समाचार-पत्रों और संगठनों में वे कार्य करते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आकाशवाणी के कर्मचारी और यह मंत्रालय उन का उपयोग करते हैं। देश में जिस विचारधारा को वे अपने माध्यम से प्रसारित करते हैं, उस विचारधारा को आज देश में सभी व्यक्ति जानते हैं कि उस के पीछे कौन सा पुट है। जैसे स्पाटलाइट है और इसी प्रकार जो दूसरा आज का प्रसंग है उन में कौन कौन व्यक्ति हैं जो कि उन के लेखक और प्रचारक हैं? मैं चाहूँगा कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय उस की तह में बैठ कर इस बात की जानकारी लें।

इसी तरह से वहां पर एक सम्प्रदायवादी लोगों का गुट भी बन गया है। अभी कुछ दिन पहले शेख अब्दुल्ला छूटे। मैं पूरी सरकार की इस ना समझी की ओर अभी नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आकाशवाणी की चर्चा करना चाहता हूँ। उस के छूटने के बाद आकाशवाणी ने जिस तरह से उस को हीरो बना कर देश में पेश किया और जिस तरह से 15-15 मिनट के समाचार बुलेटिनों में पहले 5 या 7 मिनट शेख अब्दुल्ला के सम्बन्ध में दिये, उस से यह प्रतीक होता था कि आकाशवाणी के अन्दर कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं जो इन परिस्थितियों का लाभ उठा रहे हैं।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

केवल यहीं तक नहीं। आप एक बात और देखिये। अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लड़के का विवाह हुआ। उन के विवाह के सिलसिले में हैदराबाद हाउस में जो दावत हुई उस से सम्बन्धित जो समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किया गया उस में यह कहा गया कि वहां पर राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे, राज्यों के राज्यपाल थे, संसद् के सदस्य थे, और शेख अब्दुल्ला भी मौजूद थे। मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि एक वह व्यक्ति जिस के ऊपर सरकार ने अपराध लगा कर पहले जेल में रक्खा, फिर दूसरी बार जेल में रक्खा, तीसरी बार जेल में रक्खा और पता नहीं किसी विदेशी या किसी और प्रकार के दबाव में आ कर मुक्त किया है, उस को आकाशवाणी इस प्रकार देश के सम्मुख पेश करता है जैसे वह कोई विजयी नेता है। आकाशवाणी के अन्दर जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है मुझे उस की घोर निन्दा करनी है और मैं चाहता हूँ कि इस के सम्बन्ध में सूचना मन्त्री ध्यान दें।

दूसरी सब से बड़ी चीज जो आकाशवाणी के सम्बन्ध में है वह यह कि वहां एक इस प्रकार का भी गुट है जो जान बूझ कर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा कर रहा है, विशेषकर हिन्दी की। मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रधान श्री निजलिंगप्पा ने अपना एक वक्तव्य दिया, जिस में उन्होंने कहा कि अब मैं आगे से हिन्दी में भाषण देने का यत्न करूंगा। आकाशवाणी पर जब यह समाचार प्रसारण के लिये गया तो समाचार विभाग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने नोट चढ़ा दिया कि इस समाचार को प्रसारित न किया जाये। यह 4 मार्च, 1968 की बात है। उस के अगले ही दिन 5 मार्च, 1968 को राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया ने कहीं किसी सभा में कहा कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जायेगी। इस के लिये विशेष रूप से आदेश दिया गया कि इस समाचार को प्रसारित किया जाय। अब आप यह बतलाइये कि यह योजनाबद्ध ढंग से कार्य चल रहा है या नहीं ?

18.22 hrs.

[Shri G. S. Dhillon *in the Chair.*]

इस के अतिरिक्त कुछ दूसरी चीजें भी मैं आप से कहना चाहता हूँ। हिन्दी समाचार विभाग को सम्पादन और समाचार संकलन के दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने की पहले योजना बनाई गई थी। लेकिन 1962 के बाद उस में जो पद समाप्त किये गये उन में एक प्रधान सम्पादक का पद था, दो समाचार सम्पादकों के पद थे, छः सहायक समाचार सम्पादकों के पद थे, आठ उप-सम्पादकों के पद थे। लेकिन अंग्रेजी के पदों को समाप्त करने के बजाए एक डिप्टी डायरेक्टर का पद और पांच और डायरेक्टरों के पद और अभी कुछ समय पूर्व एक ज्वायंट डायरेक्टर का पद नया बनाया गया। हिन्दी के सम्बन्ध में तो यह कहा जाता है कि पैसे का अभाव है इसलिए खर्चे में कमी की जा रही है। लेकिन जब अंग्रेजी का सवाल आता है तो सरकार के खजाने में पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है।

दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के लिए आल इंडिया रेडियो की ओर से दो व्यक्ति वहां पर भेजे गए हैं जो समाचारों का संकलन करते हैं और उन को यहां भेजते हैं। मैं सूचना मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो समाचार उनके आते हैं, जो वहां के समाचारपत्रों को पढ़ कर उन के उद्धरण वे यहां समाचारों के रूप में आपके पास भेजते हैं उनकी जो उपयोगिता है उसको आप अपने उत्तर में हमें बतायें। उनके द्वारा भेजे गए समाचारों का कितने प्रतिशत आपने उपयोग किया है ? इन दोनों देशों और दोनों प्रकार के समाचारों

के लिए आप मुख्यतः बी बी सी पर ही निर्भर करते हैं। जब यह स्थिति है तब इतना पैसा अंग्रेज़ी के सम्वाददाताओं पर व्यय करना यह कहां की समझदारी और बुद्धिमत्ता है? यह मेरी समझ में नहीं आता है।

1965 के बाद स्थिति यह है कि संविधान की दृष्टि से हिन्दी प्रमुख राज भाषा है और अंग्रेज़ी सह भाषा है। लेकिन आकाशवाणी ही केवल मात्र एक ऐसा विभाग है जहां हिन्दी क्षेत्रीय भाषा है और अंग्रेज़ी प्रमुख भाषा बनी हुई है। आप देखें कि जहां तक अंग्रेज़ी के बुलेटिनों का सम्बन्ध है उन का तो अखिल भारतीय प्रसारण होता है लेकिन हिन्दी के जो बुलेटिन हैं उनका क्षेत्रीय प्रसारण होता है। मैं उन मित्रों की उस भावना से सहमत हूं कि हिन्दी के बुलेटिनों के प्रसारण का अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय भाषाओं के जो कार्यक्रम हैं, उन में किसी प्रकार से समय में कटौती की जाए। क्षेत्रीय भाषाओं के जो कार्यक्रम हैं, उन में किसी प्रकार की कटौती न की जाय। लेकिन हिन्दी को संविधान में जो स्थान दिया गया है उसको देखते हुए और इस बात को देखते हुए भी कि देश का कोई कोना भी इस प्रकार का नहीं है जहां हिन्दी जानने वाले न हों आप का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हिन्दी के समाचार बुलेटिनों को उसी प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित करें और इस को महत्व का स्थान दें विविध भारती कार्यक्रम में प्रसारित न करें। अगर विविध भारती के कार्यक्रमों में प्रसारित करना ही है तो अंग्रेज़ी के बुलेटिनों को लें और जिन को अंग्रेज़ी समाचार सुनने हों वे विविध भारती का स्विच आन कर लें। हिन्दी को उस में स्थान देना समझ में नहीं आता है।

इसी प्रकार से उर्दू कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आकाशवाणी पर उर्दू कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तीन-तीन विभाग हैं, एक उर्दू मजलिस के नाम से है, एक उर्दू यूनिट है और एक दूसरा है। मेरा कहना यह है कि इन सब कार्यक्रमों के लिए एक संगठन होना चाहिये। अलग-अलग संगठन होने से कई कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति हो जाती है। एक संगठन होने से उनके अन्दर एकरूपता आयगी।

स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में मैं पहले भी कह चुका हूं। उनकी सर्विस के स्थायित्व के सम्बन्ध में, उनकी पद वृद्धि के सम्बन्ध में, उनकी नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ तो आप को स्थायित्व लाना चाहिये ताकि कार्य करने में उनको प्रेरणा मिले और उनका उत्साह बढ़े। जहां तक दिल्ली स्टेशन का सम्बन्ध है मुझे इस से बड़ी प्रसन्नता हुई है कि अभी कुछ दिन पहले से मैंने सुनना प्रारम्भ किया है कि दिल्ली स्टेशन ने जनता के कार्यक्रम को जैसे झुग्गी झोंपड़ी वालों की समस्या है, हर एक के पास जा जा कर उन की भाषा में उस को रिकार्ड करते हैं। इसी प्रकार से ट्रेफिक की बात है या किसी और समस्या की बात है यह जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है, जनता का प्रोग्राम जनता की भाषा में, जनता के मुंह से संग्रह करने की बात है, इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उसी तरह से मिलना चाहिए जिस तरह से धीरे-धीरे आपने देना शुरू भी किया है।

भारतीय भाषाओं की समाचार एजंसियों के सम्बन्ध में मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कुछ दिन पूर्व मुझे पता चला था कि प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को भवन बनाने के लिए 55 लाख रुपया दिया गया है। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। कुछ समय पहले यह भी निर्णय हुआ था कि यू० एन० आई० के लिए एक बुद्धिमान और एक बहुत अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए और वह की गई ताकि यह एजेन्सी किसी प्रकार से समृद्ध हो सके और देश को कुछ दे सके। लेकिन जो सुविधायें आप पी० टी० आई० या यू० एन० आई० को दे रहे हैं उसी प्रकार से भारतीय भाषाओं की समाचार एजेन्सियों को भी आपको सुविधायें देनी चाहियें, उनको भी आपको पनपाना चाहिये।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

सौभाग्य से देश में दूसरी भाषाओं की भी ऐसी समाचार एजेन्सियां हैं जिन को अखिल भारतीय एजेंसियां कहा जा सकता है। एक समाचार भारती है और दूसरी हिन्दुस्तान समाचार है। मेरा कहना यह है कि जब कि आप का उद्देश्य यह है कि भारतीय भाषाओं को धीरे-धीरे बढ़ाया जाए और समाचार पत्र जगत में भी भारतीय भाषायें आगे आ रही हैं तब इन समाचार एजेंसियों के साथ एक सौतेली मां जैसा बरताव करना कोई समझदारी या बुद्धिमत्ता की बात नही है। मैं चाहता हूं कि देश के एकीकरण की दृष्टि से उन की कमर पर भी आपका उसी प्रकार से पुष्ट हाथ होना चाहिए जैसा कि अंग्रेजी की समाचार एजेन्सियों के ऊपर आप का पुष्ट हाथ है।

आज एक और बात मैं विस्तार के साथ कहना चाहता हूं। अभी मैंने कुछ देशों में जा कर देखा है। हमारे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस की साक्षी देंगे कि अरब देशों में, इजराईल में तथा और भी कई स्थानों में भारतीय फिल्में पर्याप्त लोकप्रिय हैं। वहां होटलों में भारतीय फिल्मों के गाने चलते हैं और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उन को सुनते हैं। तेहरान में मैंने देखा है कि संगम फिल्म को चलते वहां कोई नौ महीने हो गये हैं। इसी तरह से काबुल में भी यह फिल्म चली। वहां जिस समय यह फिल्म चली तब पाकिस्तान में चूंकि भारतीय फिल्मों को दिखाया नहीं जाता है, इस वास्ते पेशावर से लोग स्पेशल पास्पोर्ट ले कर इस भारतीय फिल्म को देखने के लिये काबुल आए। इन फिल्मों के जो वितरक हैं तथा जो दूसरे देशों में जाकर उन की भाषा में इनका अनुवाद करते हैं लेकिन चित्र सारा उसी प्रकार का रहता है वे यहां से हमारी फिल्मों को खरीद लेते हैं और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा इससे कमाते हैं। भारत सरकार को चाहिये कि क्या आपके घर में कुछ इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं जो इस काम को कर सकें। यह विदेशी मुद्रा का लाभ अगर हमारे देश को ही प्राप्त हो और हमारे देश की ओर से इस प्रकार का वितरण कार्य किया जाए तो मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही उपयोगी कार्य होगा।

जहां तक समाचारों का सम्बन्ध है, एक बात की ओर मैं विशेष रूप से आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जितने भी समाचार बुलेटिन हैं उन में कभी-कभी ऐसा होता है कि विदेशी समाचारों की भरमार रहती है और उन में भी कुछ छोटे स्तर के समाचार होते हैं। एक बार समाचार प्रसारित हुआ कि फलां आदमी की एक बिल्ली ने नौ बच्चे दिये। इस तरह के विदेशी समाचार और आकाशवाणी के मुख्य बुलेटिन के अन्दर प्रसारित हो, यह समझदारी और बुद्धिमता की बात नहीं है। आप इस विभाग को थोड़ा सम्भालिये और उस में भारतीय समाचारों को महत्ता दीजिये। विदेशी समाचार अगर देने ही हैं तो जरूर दीजिये, कोई इन्कार नहीं करता है। लेकिन जो प्रमुख-प्रमुख समाचार हैं जैसे अभी अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने निर्णय की घोषणा की थी उसको दीजिये या इसी तरह के कोई और दीजिये। उसको प्रमुखता दें यह बात तो समझ में आती है। लेकिन जो बुलेटिन है उनको विदेशी समाचारों से प्रारम्भ किया जाए और भारतीय समाचारों को बाद में दिया जाए, यह बात समझ में नहीं आती है। भारतीय समाचारों को प्रमुखता दी जानी चाहिये। विदेशी समाचार जो आवश्यक हैं वे ही आने चाहियें। भारत की जनता भारतीय समाचारों से परिचित होना चाहती है।

देश में राष्ट्रीयता का उदय हो रहा है। इन समाचारों में जहां भारतीय समाचारों को प्रमुखता दी जाय वहां सारा ध्यान केवल राजनीति पर ही केन्द्रित न किया जाए। आज हमारे समाचार बुलेटिनों में समाजिक समाचार या सांस्कृतिक समाचार और देश की अन्य भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले समाचारों

का सर्वथा अभाव है। जबकि देश में इस प्रकार की भावना बढ़ रही है और देश उन से भी परिचित होना चाहता है। इस वास्ते इस ओर भी आप ध्यान दें।

मुझे विश्वास है कि सूचना मन्त्री मेरे इन सभी सुझावों पर गम्भीरता से निर्णय लेंगे और आकाशवाणी को एक स्वस्थ संगठन बनाने का कार्य करेंगे।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : बहुत से माननीय सदस्यों ने कई बातें कही हैं। उन में से एक बात पर मैं जोर देना चाहती हूं। खास तौर पर जो आबसीन पिक्चर्ज हैं और जो एडवर्टिजमेंट्स हैं उनके बारे में मैं कहना चाहती हूं। कई बार पहले भी इन के बारे में कह चुकी हूं और कई माननीय सदस्य भी इस के बारे में अपनी राय प्रकट कर चुके हैं। हमारे मन्त्री महोदय भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर के हामी हैं। इस वास्ते इस तरह की बात कहते हुए जरा संकोच होता है। हमारे इस विभाग के मन्त्री इसी देश की मिट्टी में पले हैं और छोटे से देहात से आते हैं। इस बात को उन्हें बतलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिये कि हम लोगों की क्या अर्ज है और हम क्या चाहते हैं। किस ओर हम देश को तथा अपने बच्चों को, भावी पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। हम मानते हैं कि फिल्में आदमी को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। विनोबा भावे जी ने तो खुद इसके बारे में आन्दोलन चलाया था कि ये जो आबसीन पोस्टर्स हैं इन को हटा देना चाहिये। इसके बारे में बहुत बार बहस हुई है और इन से पहले जो इस विभाग के मंत्री थे उन्होंने कहा था कि वह इसके बारे में कुछ लैजिस्लेशन लायेंगे। लेकिन पता नहीं आज तक क्या इसके बारे में किया गया है। अगर कुछ हुआ भी है और कुछ कारवाई की भी गई है तो हमें उसका पता नहीं। लेकिन हम यह जानते हैं कि इस सुझाव की कार्यान्विति नहीं हुई है। जब हम स्टेट्स से विरोध करते हैं, शिकायत इस तरह की करते हैं कि ऐसी पिक्चर्ज या ऐसे पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिये तो वे कहती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई लैजिस्लेशन नहीं है कि हम इनको हटा सकें। सारे देश के दिल की यह पुकार है और इस के बारे में मैं चाहती हूं कि कुछ किया जाय। अगर कुछ किया गया तो हमारे देश का चरित्र ऊंचा उठेगा, जो नई पीढ़ी बनने जा रही है उसके ऊपर बहुत भारी असर होगा। फिल्में हों या कोई भी मनोरंजन का साधन हो, उसका प्रभाव व्यापक तौर पर जनता पर पड़ता है। आप ने टेलीविज़न भी चलाया है। हमें भी कभी-कभी इस को देखने का मौका मिल जाता है। पता नहीं इस में क्या बताते हैं। हम पूरी की पूरी अमरीका आदि देशों की नकल कर रहे हैं।

अगर किसी बात की नकल करने से फ़ायदा होता है, तो वह बात कर ली जाये, लेकिन इस सम्बन्ध में अमरीका आदि देशों की नकल करने से देश या जनता को क्या फ़ायदा है? स्थिति यह है कि दूसरे देश जो बात छोड़ देते हैं, उस को हम शुरू कर देते हैं।

कहा जाता है कि यह देखना सैन्सर बोर्ड का काम है कि कौन सी पिक्चर एक्सहिबिट की जा सकती है और कौन सी नहीं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस बारे में डायरेक्शन दिया जाना चाहिए कि दृश्यों आदि के प्रदर्शन में फ़िल्म-निर्माता अमुक सीमा से आगे नहीं जा सकते हैं और अमुक प्रकार की फ़िल्में एक्सहिबिट की जा सकती हैं और अमुक प्रकार की नहीं। इस बारे में स्पष्ट नियम आदि बनाए जाने चाहिए।

यही स्थिति पोस्टर्ज की है। अगर हम किसी आबसीन पोस्टर के बारे में ध्यान दिलाते हैं, तो केन्द्रीय सरकार, स्टेट्स और पुलिस सब अपनी लाचारी प्रकट करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगी कि पोस्टर्ज के बारे में भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि अश्लीलता और नग्नता प्रकट करने वाले पोस्टर न प्रदर्शित किये जा सकें। इस देश में हर एक को चाहे कुछ भी

[श्रीमती जयाबेन शाह]

प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हमारी जो संस्कृति है, उसका महत्व न केवल इस देश के लिए है, बल्कि एशिया और दुनिया भर के लिए है। अगर हम इस अपनेपन को नहीं बनाए रख सकते हैं, अपने कल्चर की रक्षा और उस का प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो यह मिनिस्ट्री अपने काम में असफल समझी जायेगी और इस से देश को भी बहुत नुकसान होगा।

जहां तक इम्पोर्टिड फ़िल्म्स का सम्बन्ध है, अगर विदेशों से कोई अच्छी फ़िल्म यहां पर आए, तो कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन इस मिनिस्ट्री को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिये कि इस देश में बाहर से कैसी फ़िल्मस लाई जायें और दिखाई जायें। इस सम्बन्ध में सरकार का पूरा कन्ट्रोल होना चाहिये। सम्भव है कि इस देश में ऐसे भी लोग हों, जो हर प्रकार की फ़िल्म देखने के लिये तैयार होंगे, लेकिन इस का अर्थ यह नहीं हैं कि इस देश के सभी लोग हर प्रकार की, यहां तक कि आपत्ति-जनक, फ़िल्म्स भी देखने के इच्छुक हैं। न ही इस का अर्थ यह है कि बाहर से इस प्रकार की आपत्तिजनक फ़िल्म्स यहां पर ला कर प्रदर्शित की जायें। लेकिन मैं देखती हूं कि इस सम्बन्ध में भी सरकार की ओर से लाचारी और विवशता ही प्रकट की जाती है। सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि इस देश में बाहर से कौन सी फ़िल्म आये और कौन सी न आये।

माननीय सदस्य, श्री पाटिल, ने कहा है कि रेडियो प्रसारणों में एड्वरटाइजमेंट का समय बहुत कम है, उस को बढ़ाया जाये। मैं इस के ख़िलाफ हूं। क्या यह रेडियो का कोई उचित उपयोग है ? एड्वरटाइजमेंट्स के द्वारा पैसा तो कमाया जाये, लेकिन उन की स्क्रिप्ट्स की भी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जो कुछ भी ब्राडकास्ट करने के लिये दिया जाये, उस को ब्राडकास्ट कर दिया जाये। आख़िर एड्वरटाइजमेंट्स में विभिन्न चीजों आदि का ही प्रचार होना है। इस लिये उन का समय यथा-सम्भव कम किया जाना चाहिये।

इस मंत्रालय की ओर से हर एक स्टेट में फील्ड पब्लिसिटी आफ़िसर का दफ़्तर रखा गया है। मैं गुजरात से आती हूं। मैं—और मैं समझती हूं कि और भी लोग—उस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। किसी बड़े जल्से में कोई पब्लिसिटी आफिसर जाते हैं। उन की क्या ज़रूरत है। उन का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वे किसी से मिलते-जुलते नहीं हैं और बिल्कुल आइसोलेटिड से रहते हैं। अगर इन दफ़्तरों को ख़त्म कर के उन का काम स्टेट्स के पब्लिसिटी के दफ़्तरों को सौंप दिया जाये, तो कोई नुकसान नहीं होगा।

वित्त मंत्री ने छोटे पीरियाडिकल्ज़ और पेपर्ज़ पर स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी है। इस से उन को बड़ा नुक्सान होगा। जो नये पेपर निकल रहे हैं, जो न्यूज़-पेपर्ज़ हैं, उन की आमदनी या सर्कुलेशन ज्यादा नहीं हो सकती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह वित्त मंत्री को कहें कि इस स्टैम्प ड्यूटी को हटा दिया जाये और उस में जो वृद्धि की गई है, उस को ख़त्म कर दिया जाये।

हिन्दी के प्रयोग और प्रचार के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है। यह ठीक है कि हिन्दी के बारे में हमारे देश में कुछ झगड़ा हैं। लेकिन इस में कोई सन्देह नहीं है कि एशिया के सब देशों पर उस का प्रभाव है। अफ्रीका के कई देशों में हिन्दी फ़िल्म्स और गीत बहुत लोकप्रिय हैं। इस लिये हिन्दी के प्रयोग और उस के प्रचार के बारे में एपालेजिटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिये कि अगर वह हिन्दी का प्रयोग करेगी, तो दक्षिण वाले क्या कहेंगे। आज स्थिति यह है कि आकाशवाणी में हिन्दी न्यूज को बिल्कुल इनसिग्नीफ़िकेंट समझा जाता है, उन को कोई इम्पार्टेन्स नहीं दी जाती है।

मंत्री महोदय को इस ग्रोर भी ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक न्यूजप्रिन्ट का सम्बन्ध है, यह शिकायत की जाती है हमारे पेपर्ज को कागज नहीं मिलता है । यह सही बात है । हमारे देश में यह मान लिया गया है कि जिस पेपर का ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेशन है, वह एक ग्रच्छा पेपर हैं । यह क्राइटेरियन गलत है । इस के स्थान पर यह क्राइटेरियन बनाया जाना चाहिये कि किसी पेपर को वास्तव में कितने लोग पढ़ते हैं । ग्राज ग्रगर कोई भी नया पेपर निकालना चाहें, तो उस को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है । लेकिन सब पेपर ग्रपने पूरे कागज का उपयोग नहीं करते हैं ग्रौर उस को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं । इस की जांच करने वाला कोई नहीं है । सरकार को यह देखना चाहिये कि जब हमारे यहां कागज की स्केर्सिटी है, तो उस का उपयोग इस ढंग से किया जाये कि हमारे लोगों को इनफ़र्मेशन ग्रौर न्यूज समुचित प्रकार से मिलें ग्रौर हमारे देश का हित हो ।

ग्राखिर में मैं फिर कहना चाहती हूं कि ग्राबसीन पिक्चर्ज ग्रौर पोस्टर्ज पर पाबन्दी जल्दी से जल्दी लगाई जानी चाहिए । ग्रगर इस के लिये लेजिस्लेशन की जरूरत हो, तो वह भी जल्दी से जल्दी लाया जाना चाहिये ।

MR. CHAIRMAN: Shri Nayanar. Your party's time is only seven minutes. I hope, you will confine yourself to this time limit. As you want to leave tonight—so is Shri Sambhali—I have given you preference over others.

SHRI E. K. NAYANAR (Palghat): Mr. Chairman, I oppose the demand put forward by the Ministry of Information and Broadcasting. Rs. 25 crores have been demanded by the Ministry of Information and Broadcasting for this year to boost the propaganda of the ruling party. The radio, the press and various other media are all purposefully used in our country to praise the bankrupt plans and the heinous collaboration agreements with foreign monopolies. The Ministry is virtually functioning as the department of the AICC. That is my opinion.

Our friends on the other side may say that there are programmes of music and songs. Yes, there is music and songs, but they are used to give a sugar coating to the propaganda of the Congress Party. In the absence of an entertainment programme nobody will listen to the All India Radio. That is why they are using some songs.

If there is a rally of more than one lakh people collected by the Opposition parties, we can never hear that news over the All India Radio. For example, the Communist (Marxist) Party conducted a rally of 3 lakhs on January 3 last and the Muslim League mobilised about a lakh of people in Calicut, but you did not hear that news. You cannot hear the news from the All India Radio about a rally by the Opposition parties, whether it is the Right Communist Party, the SSP, the Muslim League, the Communist (Marxist) Party or any other Opposition party. But you can hear it for 10 minutes or 15 minutes if a Minister addresses 100 persons. Again and again you will hear the same speech. It will be tape-recorded and the listeners will be forced to hear it. That is why I accuse the AIR of functioning as the department of the AICC.

The topheavy administration of the AIR is suited to the requirements of the ruling party. While thousands of artistes, who entertain millions of people, are paid paltry sums as honoraria, these bureaucrats are drawing fat salaries without contributing much to the cause of the nation. Many artistes even do not get a chance without paying a heavy bribe to the programme directors. Without bribe they will not get a chance. It is known in this country, not in documents.

The employees of All India Radio have, naturally, got various complaints about the working of the apparatus. Recently, they have been agitating to meet their pressing demands. But the Ministry is so misinformed about the trade union rights that the demands of these employees are still being kept pending for a long time. The AIR artistes have put forward these demands, namely, recognition of AIR Broadcaster's and Telecaster's Guild as the sole bargaining Agent for Staff Artistes, immediate implementation of all the assurances given in Parliament by the Prime

[Shri E. K. Nayanar]

Minister, Mrs. Indira Gandhi on November 3, 1964—now it is 1968, that is, 4 years before—proper job evaluation for all the categories of staff Artistes by an independent agency and revision of pay scales and immediate acceptance and implementation of the charter of demands already submitted by the Guild.

While the ordinary employees are given callous treatment, the high-ups are not subjected to any scrutiny. This has resulted in the influence of foreign agencies including the CIA in the official propaganda machinery. I put a question in the last session about one top official of the AIR—it is Mrs.— as having contacts with CIA and asked if the news is correct. But without any proper enquiry, I got a denial of that. Some of the top officials have been in league with foreign Embassy personnel. The Government has only to see close relations of some AIR officials who have visited USA or other Western countries. Not only that.

The All India Radio coverage news of Vietnam people's liberation war was full of American orintation and it failed to depict the heroism of the Vietnamese freedom fighters. Equal emphasis was given to repeating Voice of America broadcasts to minimise the achievements of the National Liberation Front fighters. I remember here Mr. Karanjia's incident. He asked to give a talk on the All India Radio on Vietnam on the return of the Vietnam visit. But he did not get a chance. That was published in his weekly *Blitz*. They are depicting the voice of America about the Vietnam struggle and blackmailing the Vietnam struggle against the colonial people and the fighters of the Vietnam liberation struggle. Though the Government has scrapped the Voice of America deal due to public pressure, the Information and Broadcasting Ministry still continues to harbour "Voice of America" in disguise.

During 1967, the Central Board of Film Censors granted certificates to 1,395 films while it granted certificates only to 1,159 Indian films which shows that in our country more foreign films are in circulation than Indian ones. The foreign films are corrupting our young generation and creating a basis of American way of life in India. This has affected our Indian films too which are copying these foreign films for the sake of money.

The conditions of Cine employees are extremely bad but no legislation has been introduced so far. While leading film stars are being paid huge money, as has been already explained by some of the Members here, the films employees and technicians are ill paid and there are no rules governing their working and living conditions. But the Ministry is more concerned with the problems of producers, distributors and well known stars. Cinema industry is in crisis.

The Children's Film Society has been criticised several times in the press. Instead of producing more films for the children, the Society has produced only statistics. The record of this Society in relation to the amount spent is simply shocking.

In the past, the Information and Broadcasting Ministry has paid lakhs of rupees to Bharat Sevak Samaj in the name of publicity. The Government has discontinued this because the Bharat Sevak Samaj failed to submit audited balance sheets. But the matter should not be allowed to end there. How this notorious Samaj has spent this money must be investigated fully. The persons responsible for giving such huge amount to a corrupt organisation like this must be found out and punished severely. Otherwise, the culprits will be free to indulge in such malpractices.

The Press Information Bureau is mainly giving publicity to tour programmes of Ministers and their statements on various occasions.

If you ask any information of PIB, you will never get it. It is not at all serving the public cause.

Through advertisements to Press, the Government is trying to influence the Newspapers also. The journals favourable to the ruling party are given a dose of advertisements. Even secret briefings are arranged through the PIB to selected journals on certain political developments with a view to influence these newspapers.

The long-standing demand for a high-power transmission station for Kerala has not materialised even now. Therefore...

MR. CHAIRMAN : The length of his paper is more than the length of his time. The hon. Member should conclude now.

SHRI E. K. NAYANAR : I will finish in a minute.

Therefore, these Rs. 25 crores will be spent for the cause of the propaganda of the ruling party and the capitalist and land-lord classes of this country. I am, however, sure that, despite such a colossal expenditure, the Congress Party will not be able to save its tottering image among the Indian people who are realising from their own experience that the corrupt Congress regime is bound to fall sooner or latter.

MR. CHAIRMAN : Mr. Sambhali. Since he is also leaving tonight, I am calling him. He must strictly observe the time. The moment I ring the bell, he must finish, because I have to call another gentleman from this side, Mr. Venkatasubbaiah.

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : सदर साहब, इन्फार्मेशन ऐन्ड ब्राडकास्टिंग की ग्रान्ट का मैं सख्ती के साथ विरोध करता हूं। आल इंडिया रेडियो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बल्कि दुनिया के बहुत बड़े रेडियो स्टेशनों में से है। लेकिन शायद वह अपने फैलाव में ही है, साइज में ही है, पब्लिक के लिए फायदेमन्द होने में नहीं है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी खामियां हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता था। लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, इसलिये मैं सिर्फ दो चीजों पर कन्सेन्ट्रेट करूंगा।

सबसे पहली चीज आल इंडिया रेडियो में जितनी ब्यूरोक्रैसी है, जितना वर्कर्स का अपमान और आर्टिस्टों का जितना एक्स्प्लायटेशन होता है उतना शायद किसी दूसरे विभाग में न होता हो। आप ताज्जुब के साथ सुनेंगे कि वहां के मोटर ड्राइवर्स की तनख्वाहें दूसरे मुहकमों से कम हैं लेकिन उन मोटर ड्राइवर्स से 16-16 घन्टे काम लिया जाता है। रात की ड्यूटी उनसे ली जाती है तब 16 घन्टे का काम लिया जाता है और जब अपनी रिप्रेजेन्टेशन वह मिनिस्टर साहब से करने की कोशिश करते हैं तो वहां की ब्यूरोक्रैसी उनको मिलने की भी इजाजत नहीं देती है। अगर मिनिस्टर साहब चाहें तो मैं उनके बारे में लिखकर आपके पास पहुंचा दूं। मेहरबानी करके उनकी फरयाद को सुनिये। आर्टिस्टों का तो हाल ही वहां पर निराला कर दिया गया है। समझ में नहीं आता कि वह बेचारे रेडियो आर्टिस्ट हैं, वर्कर हैं या किसी ठेकेदार के अमानी के तौर पर काम करने वाले मजदूर हैं बल्कि उनसे भी वे बदतर हैं। अजीब हाल है। आपने किसी दूसरे मुहकमे में ऐसा नहीं सुना होगा कि सारा काम वहां कान्ट्रैक्ट बेसिस पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? बहाना यह लिया जाता है कि हम उनको ज्यादा पे करते हैं इसलिये कान्ट्रैक्ट बेसिस पर उनसे काम लेते हैं। अगर 80 रुपये भी पे कर दिया गया और महीने में एक दिन काम लिया गया तो बताइये किस तरह से आपको अच्छे आर्टिस्ट मयस्सर हो सकते हैं। लेकिन भला हो इस बेकारी का कि ऐसी हालत में भी वे बेचारे इस डिपार्टमेन्ट में पड़े हुये हैं और बरबाद हो रहे हैं, उनके बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं लेकिन बड़े हुए हैं क्या करें। मेरी समझ में नहीं आता कि कान्ट्रैक्ट सिस्टम को क्यों नहीं आल इंडिया रेडियो से खत्म किया जाता? आज हमारे जो मंत्री जी हैं, शाह साहब, वह तो किसी जमाने में इस चीज के बहुत ज्यादा कोशिश में रहे हैं कि कान्ट्रैक्ट सिस्टम, बिल्डिंग और कांस्ट्रक्शन विभाग से भी खत्म किया जाये। लेकिन ताज्जुब है कि उनके होते हुये इस डिपार्टमेन्ट में कान्ट्रैक्ट सिस्टम मौजूद है। अगर अच्छा स्टाफ लाना है, अच्छे आर्टिस्टों को रखना है तो जरूरत है इस बात की कि बजाय कान्ट्रैक्ट सिस्टम के उनको रेगुलर सर्वेन्ट डिक्लेयर किया जाये। उनकी सर्विस रेगुलराइज की जाये। जो उनकी संस्था है उनको रिकग्नाइज किया जाये, उनके लिये

[श्री इसहाक़ सांम्भली]

ऐक कमीशन मुकर्रर किया जाये और इसके साथ साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि एक आल इंडिया रेडियो सर्विस कायम की जाये।

जिस से कि इस डिपार्टमेन्ट की इम्पोर्टेन्स बढ़े और वह ब्राडकास्टिंग सर्विस इन आर्टिस्टों को सिलेक्ट करे, सिलेक्ट करने के बाद उन में से लोगों को लिया जा सके ताकि ब्यूरोक्रेसी की इस वक्त जो बादशाहत है, वह बादशाहत न रह सके। यह न हो कि जो कोई उन के पांव छूएगा उस को काम मिल सकेगा और जो नहीं छू सकेगा, उस को रुखसत कर दिया जायेगा। आज यह चीज वहां पर देखने में आती है। अगर मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो मैं उन्हें लिख कर भी भेज सकता हूँ।

एक चीज की तरफ़ मैं खास तौर से तवज्जह दिलाना चाहता हूँ—वह है फिल्म इण्डस्ट्री फिल्म इण्डस्ट्री के बारे में यहां पर अभी काफ़ी जिक्र हुआ है। मैं इस वक्त पूरी फिल्म इण्डस्ट्री के बारे में तो नहीं कहूँगा क्योंकि उस के लिये बहुत वक्त चाहिये, लेकिन यह सही है कि मौजूदा फिल्मों को बना कर, खास तौर पर मौजूदा हिन्दी फिल्में जिस स्टैण्डर्ड की बन रही हैं, उन से हमारे नौजवानों के इखलाक को बिगाड़ा जा रहा है—इस में दो रायें नहीं हैं। फिल्म इण्डस्ट्री में जहां एक तरफ़ उन लोगों के नाम हैं जोकि करोड़ोंपति हैं, मैं करोड़पति नहीं कह रहा हूँ, करोड़ोपति कह रहा हूँ, वहां दूसरी तरफ उन लोगों की हालत काबिले-रहम है, जो एक्सट्रा आर्टिस्ट कहलाते हैं। आप बम्बई में जाकर देखें, उन के बच्चे भूखों मरते हैं, लेकिन न जाने किस उम्मीद में वहां पर पड़े हुए हैं, बेकारी का भला हो, मजबूरी की हालत में फ़ाके कर रहे हैं। आज अगर किसी की मेहनत से फिल्म बनती है तो उन्हीं एक्सट्रा आर्टिस्टों की मेहनत से फिल्म तैयार होती है, सब से ज्यादा मेहनत उन्हीं को करनी पड़ती है, उनकी मेहनत की बदौलत फिल्म बनाने वालों की जेबों में पैसा आता है, लेकिन उन की तरफ़ सरकार की तवज्जह नहीं है। सरकार को बार बार रिप्रेजेन्टेशन्ज दिये गये, तवज्जह दिलाई गई, लेकिन सरकार ने आज तक उन के लिए कोई कानून बनाने का इन्तजाम नहीं किया, आज तक उन की हिफ़ाजत और प्रोटेक्शन का कोई इन्तजाम नहीं किया गया। एक्स्ट्रा फिल्म आर्टिस्टस वहां जाते हैं और जल्दी मौत का शिकार हो जाते हैं, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं लेकिन उन जालिम प्रोडयूसरों और बड़े बड़े पैसे वालों से बचाने का कोई इन्तजाम नहीं है। यह क्यों है? यह इस लिये है कि फिल्म इण्डस्ट्री जैसी इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्री प्राइवेट सैक्टर को दे दी गई है, इस इण्डस्ट्री को बड़े-बड़े सरमायेदारों के हाथ में छोड़ दिया गया है। जरूरत इस बात की है कि इस इण्डस्ट्री को नैशनलाइज किया जाय, जरूरत इस बात की है कि आल इण्डिया रेडियो को वह शक्ल दी जाय, जिससे कि सही मायनों में वह हिन्दुस्तान की एक ऐसी सर्विस बन सके, वह कारपोरेशन बन सके जिससे कि उसकी सही शक्ल मुल्क के सामने आ सके। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस अहम प्रोजेक्ट को ऐसे लोगों के हाथों में छोड़ दिया गया है मैं उन के नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर इजाजत देंगे तो उन के नाम भी ले दूंगा—जिन के बारे में अभी यहां पर जिक्र हुआ है कि उन का एशिया फाउन्डेशन से ताल्लुक था, और भी कुछ बातें उन के बारे में कही गई, मैं उन के बारे आप को इत्तिला दे दूं कि वह बहुत बड़े ओहदेदार बन कर अनकरीब जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? टाटा के यहां जा रहे हैं। क्या पब्लिक सैक्टर की चीज को, हमारे इतने इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट को ऐसे लोगों के हाथों में दिया जाना चाहिये।

आखिर में मैं मिनिस्टर साहब का दो चीजों के लिये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आल इण्डिया रेडियो में जहां ज्यादातर चीजें शिकायत की हैं, बाज चीजें अच्छी शुरू की गई हैं, मिसाल के तौर पर उर्दू का जो प्रोग्राम

होता है, मैं कह सकता हूँ कि उस की वजह से रेडियो का इस्तेमाल बढ़ा है, रेडियो की तरफ लोगों की तवज्जह बढ़ी है। जो मुशायरे ब्राडकास्ट होते हैं, उर्दू मजलिस में जो प्रोग्राम दिया जाता है, खुशी की बात है कि उस की वजह से रेडियो की मकबूलियत बढ़ी है। लेकिन इस के साथ साथ मैं यह कह सकता हूँ कि अंग्रेजी की आज भी वहां पर इम्पोर्टेन्स है। नैशनल इन्टीग्रेशन जैसे मसले पर दिल्ली के आल इण्डिया रेडियो के स्टेशन से टाक अंग्रेजी में होती है, लेकिन हिन्दुस्तान की किसी जुबान में नहीं होती है। जरूरत इस बात की है कि इस तरफ़ तवज्जह दी जाय।

मैं आप से अर्ज करूंगा कि आर्टिस्टों की हालत को सम्भालिये, नीचे के वर्कंज की हालत को सम्भालिये, वरना वह उबाल उठेगा कि जिस पर आप काबू नहीं रख सकेंगे मुझे ताज्जुब है कि हमारे तजुर्बेकार मिनिस्टर और इतनी प्रोग्रेसिव डिप्टी मिनिस्टर के होते हुए वहां पर आर्टिस्टों पर जुल्म हो रहा है और वह उस को खामोशी से बरदाश्त कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों की तरफ़ आप पूरी तरह से ध्यान देंगे।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I rise to support the Demand for Grants of the Ministry of Information and Broadcasting. This is a very important Ministry and it has a very historic role to play in the present context of things. I personally feel that more time should have been allotted for discussion of this Ministry in the House so that the various aspects of its functioning could have been very well highlighted on the floor of the House.

As I have already submitted to you, this Ministry should not be taken as though it is only a sort of passing bureau or information bureau for the various actvitities of the Government of India. In my opinion, this Ministry has powerful media, through the AIR and other units, to give a correct and proper perspective of the socio-economic activities being undertaken in this country both on behalf of Government and through several other organisations.

In this connection, I would like to bring to the notice of the hon. Minister the working of the units of this Ministry.

For instanc, the AIR with its various regional siations and offices in various parts of the country, should be more effective and more streamlined. At the present juncture, our country is passing through a very critical phase in its onward march:

MR. CHAIRMAN : He may resume his speech tomorrow. The House stands adjourned to meet at 11 A.M. tomorrow.

19.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 17, 1968/ Chaitra 28, 1890 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Daryaganj, Delhi-6.